पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून, रविवार 11 जुलाई 2021

पेज 8

सीएम धामी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से की भेंटसे भेंट करते हुए।

नीति और नेलोंग घाटी को इनर लाईन प्रतिबंध से हटाने का किया अनुरोध

■ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की

■ 02 एयर एंबुलेन्स, गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना का किया आग्रह

अनुरोध

आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने की स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का भी अनुरोध

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड राज्य में समय–समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलोंध्पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती/व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी के राज्य की भाँति (केन्द्रांश रू राज्यांश) 90 रू 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के

सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में समय–समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि रूपये 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढने से वहां से पलायन रूकेगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलोंग घाटी (जाडूंग गांव) को इनर लाईन प्रतिबन्ध से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा की अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संदर्भित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के लिये 02 एयर एंबुलेन्स, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना, चार धाम यात्रा, कांवड यात्रा पर भी विचार विमर्श

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चार धाम यात्रा, कांवड यात्रा पर भी विचार विमर्श किया।

आपदा प्रभावित गाँवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने हेतु स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष घटकों के लिए दिशा–निर्देश तैयार करते समय विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों की वस्तुस्थिति पर ध्यान दिये जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

राज्य के बजट आवंटन को 150 करोड़ करने का अनुरोध किया

भेंट

■ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिये अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ

भारत मिशन–2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रूपये से बढ़ाते हुए 150 करोड रूपये करने का अनुरोध किया ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को गंभीरता से पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के 07 नगर निगमों के 08 लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की डीपीआर कुल योजना लागत रू० 126.53 करोड़, एसएचपीसी (स्टेट हाई पॉवर कमेटी) से अनुमोदित कराकर स्वीकृति के लिये भारत सरकार को प्रेषित की गई है। उक्त 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की डीपीआर हेतु रू0 48.78 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।

स्वच्छ भारत मिशन–2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को 89 करोड रूपए का बजट आवंटन किया गया है।

कालीदास मार्ग पुनर्गठन सीवर योजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश

संवाददाता देहरादून। तेजी से कम होते कोरोना के मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने देश–दुनिया के पर्यटकों को बढ़ी राहत दी है। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों में प्रवेश से पहले कोरोना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने से पर्यटक स्थल सुरक्षित हुए हैं। वीकेंड पर मसूरी और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से पर्यटक स्थल में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ अनावश्यक भीड़ को भी काबू किया जा रहा है। प्रशासन के इस निर्णय से व्यापारी पूरी तरह से खुश हैं। इससे पर्यटक स्थलों पर बढ़ रहे दबाव को भी कम किया जा रहा है। जिससे जाम की स्थिति पैदा नहीं हो रही है।

संक्षिप्त समाचार

सीएम ने किसान कल्याण मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSISAC में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सहकारी संस्थाये ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सकेंगी।

नौकरियों के लिए लिया जाने वाला आवेदन शुल्क हो माफः मोर्चा

संवाददाता विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न श्रेणी के पदों हेतु आवेदन परीक्षा शुल्क निर्धारित किया हुआ है। प्रदेश में लाखों बेरोजगार ऐसे हैं, जो नौकरियों हेतु आवेदन करने की सोचते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते नौकरियों हेतु आवेदन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको अपने अभिभावकों पर ही आर्थिक रूप से आश्रित रहना पड़ता है।

ऑनलाईन फाइनैंस करें मारूति सुजुकी स्मार्ट फाइनैंस के साथ

संवाददाता देहरादून। मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ग्राहक अब मारूति सुजुकी स्मार्ट फाइनैंस के साथ कभी भी, कहीं से भी अपनी कार को ऑनलाईन फाइनैंस करा सकते हैं। मारूति सुजुकी स्मार्ट फाइनैंस एरेना। और नेक्सा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यह सर्विस पूरे देश में उपलब्ध है और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की जरूरतों कों पूरा करने के लिए ग्राहकों की व्यापक रेंज को इस सर्विस के तहत कवर किया जाएगा। ग्राहक www-marutisuzuki-com और www-neÛaeÛperience-com के माध्यम से इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं।

भारत में 26 और 27 जुलाई को होगा प्राइम डे 2021 का आयोजन

संवाददाता देहरादून। अमेजन का वार्षिक प्राइम डे ईवेंट भारत में 26 और 27 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस सेल में ग्राहकों के लिए दो दिनों तक प्राइम के तहत सर्वश्रेष्ठ पेशकश की जाएगी। यह सेल भारत में प्राइम की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित की जा रही है। अमित अग्रवाल, एसवीपी और कंट्री मैनेजर, अमेजन इंडिया ने कहा "हम इस प्राइम डे को Amazon-in पर मौजूद लाखों एसएमबी विक्रेताओं को समर्पित करते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।